

प्रेषक,

विनीता कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

शहरी विकास विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग:

देहरादून: दिनांक- 13 अक्टूबर, 2008

विषय : नगर पालिका परिषद नैनीताल के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु वर्ष-2008-09 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या 3996/23-स्था0नि0/2008 दिनांक 25-8-2008 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, नैनीताल के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रस्तुत रु0-98.00 लाख की लागत के आगणन के विपरीत वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु0 62.43 लाख के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 62.43 लाख (रुपये बासठ लाख तिरालिस हजार मात्र) धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि रु0 62.43 लाख (रुपये बासठ लाख तिरालिस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर नगर पालिका परिषद, नैनीताल को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण एजेन्सी के अभियंता/अधिशाली अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
7. निर्माण करने एवं इस हेतु सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन कड़ाई से किया जाए।
8. निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
9. यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं, तब संबंधित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।
10. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
11. सभी कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेन्सी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किशतों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किशत तब ही निर्गत की जाये, जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
12. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशाली अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
13. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
14. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो. नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
15. उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
16. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अभियन्ता/अधिशाली अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
17. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
18. ऑपरेशन तथा मैनटीनेंस के लिए धनराशि नगर पालिका द्वारा स्वयं व्यय की जाए।
19. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन तथा शहरी विकास निदेशालय को उपलब्ध कराये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 776/XXVII(2)/2008, दिनांक- 01 अक्टूबर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 11⁴⁶ (1)/IV/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
9. अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
अपर सचिव।